



गुजरात के....
पेज 2

web: www.atulyasansar.com

आपकी खबरों का संसार...

RNI No.-RJHIN/2015/63826

संस्करण:
जयपुर

हिन्दी समाचार पत्र...

Digital Edition

www.liveworldnews.in

वर्ष: 10

अंक: 351

जयपुर, बुधवार 01 जुलाई, 2026

मूल्य: 2 रुपए

पृष्ठ: 4

राजस्थान पुलिस में...

पेज 3

मुंबई में चलती स्कूल बस पर पेड़ गिरा: बस में फंसे एक छात्र की मौत

11 घायल: सभी स्टूडेंट स्कूल से घर लौट रहे थे



मुंबई। मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर प्राइवेट स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया। बस में कुल 12 स्टूडेंट थे। उनमें से 11 का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बस में फंसे 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद प्राइवेट बस रोज की तरह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। तभी रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे लगे पेड़ की बड़ी डालियां बस की छत पर आ गिरीं, जिससे बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरह दब गया। पेड़ गिरते ही बस के अंदर मौजूद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग बस के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। मशीनों और कटर की मदद से पेड़ को काटा गया।

परिजन घटनास्थल पर पहुंचे

हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने बच्चों की चिंता में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और सभी की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ट्रैफिक को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है।

24 जून- मुंबई में बारिश से पेड़ उखड़े, कई गाड़ियां दबीं

मुंबई में 23 जून को 13 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हुई थी। इसके बाद से मुंबई में आंधी-बारिश जारी है। 24 जून को तेज बारिश के बाद अंधेरी सब-वे में पानी भर गया था। इसके बाद इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। वहीं विक्रोली वेस्ट में रिहायशी इमारत के पास बनी रेंटिंग गैलरी गिर गई थी। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए थे, जिसकी चपेट में आने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था।

बिहार-एनकाउंटर में मारे गए भगत के घर बजे देशभक्ति गीत

तेरहवीं पर मां बोली- सम्राट पर भरोसा नहीं; मांझी ने कहा- पुलिस ने सही किया



आरा (भोजपुर)। बिहार के भोजपुर में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भगत तिहारी की तेरहवीं है। करीब 25 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम है। जबकि 15 हजार और लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। श्राद्ध का भोज शुरू हो चुका है। अब तक 14 हजार लोग भोज खा चुके हैं। भगत तिहारी के घर पर देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने भ्रष्ट व्यवस्था मुर्दाबाद, बलिदानी लड़ें थे गोरों से, हम लड़ेंगे कालों से, चारों तरफ अंधेरा है, पहेरेदार लुटेरा है, शहीदों, हम शर्मिदा हैं के नारे लगाए। इधर, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भगत तिहारी के एनकाउंटर को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर कोई पिस्टल लहराएगा तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। पुलिस मर जाए तो बहुत अच्छा। अगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानने वाला मारा जाए तो सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जो किया वो सही है।

मां बोली- सम्राट और उनकी पुलिस पर भरोसा नहीं

भगत तिहारी की मां आशा देवी ने कहा कि आज बेटे का श्राद्धकर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी कोई गलती करता है, तो पुलिस तत्काल उसे पकड़ लेती है। लेकिन मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गांव में भगत का स्मारक बनना चाहिए, लेकिन मुझे बिहार सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेगी। भगत तिहारी के छोटे भाई चंदन तिहारी ने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा।

बंगाल से कश्मीर तक 1500किमी. लंबी मानसून पट्टी बनी

इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश संभव, 26 राज्यों में मानसून पहुंचा

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना। मानसून ने मंगलवार दोपहर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है। उधर, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किमी लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यह हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) के करीब स्थित है। यह ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी, उत्तर भारत में बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

समझें, मानसून ट्रफ क्या होती है

मानसून ट्रफ कम दबाव क्षेत्र की एक लंबी पट्टी



होती है, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून की रीढ़ माना जाता है। यह ट्रफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाओं को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक खींचकर लाती है। इसी वजह से देश के कई इलाकों में बारिश होती है।

असम में बाढ़, 22 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में

लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। अरुणाचल में बारिश से लेकु नदी उफान पर आ गई, जिससे असम के जोनाई इलाके में भीषण बाढ़ आ गई। नेशनल हाईवे-515 भी डूब गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, बाढ़ से राज्य के छह जिलों में 22 हजार से ज्यादा लोग

प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले में पड़ा है, जहां करीब 16 हजार लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से 96 गांव डूब गए हैं, करीब 1690 हेक्टेयर फसल और 48 हजार से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं।

6 राज्यों में गर्मी का असर, पारा 40डिग्री पार

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,

दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में मंगलवार को पारा 40डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा हरियाणा के रोहतक में 43.5डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में 43.4डिग्री, यूपी के बांदा में 43.2डिग्री, मध्य प्रदेश के खजुराहो में 41.2डिग्री, पंजाब के आनंदपुर साहिब में 40.6डिग्री और गुजरात के सुरेंद्रनगर में 40.5डिग्री रहा।

भारत में 9 करोड़ बच्चे हीटवेव की चपेट में

युनिसेफ की विल्ड्रन्स क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत में करीब 8.93 करोड़ बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं, जहां हीटवेव का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के लगभग 99.7 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी जलवायु संबंधी खतरे का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 96.2 प्रतिशत भारतीय बच्चे सूखे के खतरे वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 92 प्रतिशत बच्चे तेज गर्मी से प्रभावित हैं, जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। रिपोर्ट ने बच्चों पर बढ़ते जलवायु संकट को गंभीर चिंता का विषय बताया है।

पुणे मर्डर- क्या हुडी में दिखा व्यक्ति चेतन ही था

पुलिस चलने का तरीका जांचेगी, सिया का केस लड़ने पर 2 वकीलों का दावा

पुणे। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस करेगी। गेट एनालिसिस यानी पुलिस चेतन के चलने का तरीका, बाँड़ी मूवमेंट, कदमों की लंबाई की जांच करेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दावा है कि 18 जून को (मर्डर वाले दिन) लोहागढ़ फोर्ट पर हुडी पहने दिखा युवक चेतन ही था। इधर, मर्डर के इस मामले में नया कानूनी विवाद सामने आया है। आरोपी सिया का केस लड़ने को लेकर आशुतोष श्रीवास्तव नाम के वकील और सिया के परिवार के बीच विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल, 2 वकीलों आशुतोष श्रीवास्तव और विपुल दुशिंग ने सिया गोयल की ओर से कोर्ट में पैरवी करने का दावा किया है। आशुतोष का कहना है कि सिया गोयल ने अपना केस लड़ने के लिए उन्हें नियुक्त किया है। 29 जून को सिया के भाई साहिल ने कहा कि हमारे वकील विपुल दुशिंग हैं। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील नहीं हैं, वे हम पर प्रेशर बना रहे हैं। इसके बाद श्रीवास्तव ने साहिल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा।

दो वकीलों का विवाद कब शुरू हुआ

मामला 29 जून को सुनवाई के दौरान बढ़ा। जब वडगांव मावल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिया ने कथित तौर पर कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं। मेरी ओर से विपुल दुशिंग पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल को कानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। नोटिस में उन्होंने मांग की है कि साहिल (सिया का भाई) उनके खिलाफ दिए गए कथित बयान तुरंत वापस लें। सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें। केतन मर्डर केस में आरोपी चेतन चौधरी राजस्थान के जोधपुर के पलासनी गांव का रहने वाला है। दैनिक भास्कर ने चेतन के दोस्तों से बातचीत की है। उनके मुताबिक, चेतन के पिता की दुकान (किराना) के सामने सिया गोयल के पिता का ऑफिस है।

अमेरिकी सांसद बोले-भारत से 30 साल में सबसे खराब रिश्ते

ट्रम्प के एकतरफा फैसले ने भरोसा तोड़ा, यकीन न हो तो जयशंकर से पूछिए

वॉशिंगटन डीसी। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन में आयोजित यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट 2026 में उन्होंने कहा कि ट्रम्प की टैरिफ नीति, ईरान के साथ युद्ध और सहयोगी देशों से बिना सलाह लिए फैसले करने से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। खन्ना ने कहा मैं बातों को घुमाकर नहीं कहता। भारत-अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे निचले स्तर पर हैं। ईरान युद्ध का असर भारत में गैस की कीमतों पर भी पड़ा। अगर भरोसा नहीं है तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर से पूछ लीजिए।

खन्ना बोले- टैरिफ से भरोसे की एक पीढ़ी खत्म हो गई

रो खन्ना ने ट्रम्प की टैरिफ नीति को भी गलत बताया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में चीन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक भारतीय राजदूत से हुई। खन्ना के मुताबिक राजदूत ने उनसे कहा, 'आपके राष्ट्रपति की



वजह से भरोसे की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है।' उन्होंने कहा कि अगर ट्रम्प की नीतियों से हुए नुकसान को स्वीकार नहीं किया गया तो यह सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा होगा। रो खन्ना ने ट्रम्प को 'लेम डक' राष्ट्रपति बताते हुए दावा किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी अगले मिड-टर्म चुनाव में प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करेगी और 2028 का राष्ट्रपति चुनाव भी जीतेगी। नई पीढ़ी को अमेरिका के साथ-साथ दुनिया के देशों के साथ उसके रिश्ते भी दोबारा मजबूत करने होंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति फैंकलिन डी. रूजवेल्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वे दुनिया के देशों के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी समर्थन करते थे।

पाकिस्तान बोला- हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे: सिंधु जल संधि अब भी लागू, भारत इसे एकतरफा खत्म नहीं कर सकता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। वहीं अताउल्लाह तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अब भी लागू है। भारत इसे न तो एकतरफा स्थगित कर सकता है, न रद्द कर सकता है और न ही इसमें बदलाव कर सकता है।

सिंधु जल संधि पर सेमिनार करेगा पाकिस्तान

पाकिस्तानी मंत्रियों ने बताया कि मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार किया जाएगा। इसमें कानूनी



एक्सपर्ट, जल एक्सपर्ट्स और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। डॉन के मुताबिक, तरार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी साफ कर चुके हैं कि पानी हमारी जीवनरेखा है और यह

हमारी रेड लाइन भी है।

21 जून को PAK रक्षा मंत्री बोले थे- भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खाना आसिफ ने 21 जून को सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी वैनल न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी।

भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या है?

सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच स्टैंडस्टिल समझौता हुआ। इसके तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वलैंड बैक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरु और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है।

राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 100 पुलिस-निरीक्षकों के तबादले

सबसे अधिक पोस्टिंग अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा रेंज में, सतपाल सिंह का ट्रांसफर निरस्त

जयपुर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 100 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के तबादला आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण संबंधित अधिकारियों की स्वयं की प्रार्थना के आधार पर किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जारी सूची के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर, आयुक्तालय जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा रेंज के अलावा सीआईडी-सीबी, सीआईडी-सीबी सतर्कता शाखा, सीआईडी-सीबी सिविल राइट्स, एटीएस-एसओजी, एसीबी, जीआरपी, राजस्थान पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण निदेशालय, पीटीएस भरतपुर, पीटीएस जोधपुर, पीटीएस खैरवाड़ा, पीटीएस बीकानेर, एजीटीएफ, लीगल सेल, पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, एससीआरबी तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग सहित कई इकाइयों में कार्यरत निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला सूची में रोहिताश, मेघना त्रिपाठी, हेमलता शर्मा, तुलसीराम, नरेंद्र सिंह, सुनील



ताड़ा, मोहन सिंह, मुकेश चौधरी, छोटीलाल मीणा, रामेश्वरी, जगदीश सिंह, मुकेश चंद, करतार सिंह, प्रहलाद चंद, दिग्विजय सिंह, मुरारीलाल मीणा, सुमेर सिंह, हरिमन मीणा, हीरालाल, अजीत कुमार, कुसुमलता, तेजपाल सैनी, बच्चू सिंह, गुधिष्ठिर, कंचन कुमारी, मांगेलाल, हरलाल, दयाराम मीणा, सुरेंद्र

यादव, चौथमल बलाई, लक्ष्मीनारायण, कमल पुरी गोस्वामी, सत्यवीर, बशीलाल, महेंद्र सिंह, केशर, चंद्रवीर, अवधेश सांदू, महेश श्रीमाली, सुरेंद्र कुमार राणा, ज्ञानचंद, गंभीर सिंह, रामभरोसी मीणा, हरीसिंह मीणा, मदनलाल, हरेंद्र सिंह सौदा, आनंद यादव, मोहम्मद रफीक, माधोसिंह, दीप सिंह, प्रवीण राजपुरोहित, मिठूलाल मेघवाल, दलबीर सिंह, नेहरीलाल गुर्जर, हिमांशु सिंह राजावत, भीमसेन कौशिक, सुखवीर सिंह, प्रेमचंद, प्रदीप सिंह, विकांत शर्मा, विक्रम सिंह, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, गौरव प्रधान, सुधीर कुमार उपाध्याय, कमल किशोर, लीला कुमारी, चंपाराम मेघवाल, सुरेश कुमार सोनी, भारत सिंह, अमित कुमार, शिवदास, महीराम बिश्नोई, बेगराज मीणा, रमेशचंद मीणा, राजेश कुमार, संगीता बंजारा, सुरेशचंद मेघवाल, राजेश शर्मा, शैफाली सांखला, सरोज कुमारी, मोहनलाल, जितेंद्र कुमार गंगवानी, भरत सिंह, धर्मसिंह, अर्चना मीणा, रामकेश मीणा, भवानी सिंह राजावत, गीता कुमारी, संजू रानी, उर्मिला कुमारी, अशोक, नैकीराम, शेषकरण बारहट, मुकेश कुमार मीणा, विनोद कुमार शर्मा, अशोक कुमार सैनी, मनीषा,

रूपनारायण तथा हरिसिंह देपावत समेत कुल 100 निरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है।

आदेश के अनुसार सबसे अधिक पदस्थापन अजमेर रेंज, भरतपुर रेंज, जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, उदयपुर रेंज, कोटा रेंज, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर तथा सीआईडी-सीबी में किए गए हैं। कई अधिकारियों को एटीएस-एसओजी, जीआरपी, एसीबी, प्रशिक्षण संस्थानों और पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में भी भेजा गया है।

पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रकरण अथवा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-16 के तहत कार्रवाई विचाराधीन या प्रस्तावित है, उन्हें फील्ड में पदस्थापित नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय ने 19 जून 2026 को जारी आदेश संख्या 1521 के तहत क्रम संख्या-3 पर अंकित पुलिस निरीक्षक सतपाल सिंह का अजमेर रेंज

से पुलिस आयुक्तालय जयपुर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया है। सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों, प्रशिक्षण संस्थानों के कमांडेंट और संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजें।

बीते दिनों भी हुए थे ट्रांसफर

उस समय जयपुर के पुलिस आयुक्तालय और छ्द्र में भी कई अहम बदलाव देखने को मिला था। रमेश कुमार पारीक, ओम प्रकाश मीणा और सुरेश कुमार स्वामी को जेजीए में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती मिली। राजधानी में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए एसीपी भी लगाए गए। जबकि बीते मई महीने में 19 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए। उस समय दौसा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू सहित कई जिलों के थाना प्रभारियों व निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ था।

पूर्व एमएलए बलजीत-यादव को राहत नहीं,5 महीने से जेल में

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; विधायक निधि के दुरुपयोग और गबन का आरोप



जयपुर। बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आज पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 25 जून

को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप में 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, ईडी मामलों की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल को बलजीत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूर्व विधायक की ओर से हाईकोर्ट का रुख करते हुए जमानत याचिका दायर की गई थी।

ईडी ने कहा-गबन की राशि से संपत्तियां खरीदी

बहस के दौरान ईडी ने कहा कि इस मामले में एसीबी ने 12 दिसंबर 2024 को बलजीत यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जिन फर्मों को काम के ठेके दिए गए वो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद बनाई गई अथवा उनके जीएसटी पंजीकरण फर्जी थे। इन फर्मों के जरिए धनराशि यादव के सहयोगियों और रिश्तेदारों तक पहुंचाई गई। ईडी ने कहा कि बलजीत यादव ने गबन के 2.78 करोड़ रुपए से संपत्तियों की खरीद और राजनीतिक खर्चा किया।

यह था घोटाला

2021 में बलजीत यादव ने विधायक रहते हुए अलवर के 32 सरकारी स्कूलों में क्रिकेट बैट, बैडमिंटन किट और अन्य सामग्री खरीदी में भूमिका निभाई थी। आरोप है कि सामान ढाई-तीन गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा। सामग्री घंटिया क्वालिटी की थी। 3.72 करोड़ की हेराफेरी में यादव की भूमिका थी। इस केस में बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड, सूर्या इंटरप्राइजेज, राजपूत स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज, शर्मा स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज के संचालक व शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं।

20 साल पुराने पांचना-बांध जल विवाद पर बनी सहमति

जयपुर में किरोड़ी समेत 3 मंत्रियों ने दोनों पक्षों से की वार्ता, 6 जुलाई तक खुलेगा पानी

जयपुर। राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर जयपुर में हाईलेवल मीटिंग में मंगलवार देर रात सहमति बन गई। बांध का पानी 6 जुलाई तक खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन किए। इससे पहले शिक्षा संकुल के माधव सभागार में मंगलवार रात 8 बजे बैठक हुई थी। जिसमें सरकार के तीन मंत्रियों और दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सहमति नहीं बन पाई थी। कमांड एरिया के किसान बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए थे। इसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज होकर बाहर निकल गए थे।

रात में दोबारा हुई बैठक

दो घंटे बाद रात 10 बजे फिर से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शिक्षा संकुल के माधव सभागार में पहुंचे। यहां किरो?ी ने पांचना बांध विवाद को लेकर मंत्री सुरेश रावत और जवाहर सिंह के साथ बातचीत की। इसके बाद तीनों मंत्रियों ने दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करके विवाद को सुलझाया।

सीएम बोले- यमुना के पानी से किसान सोना पैदा करेगा: कांग्रेस पहले 1994 के समझौते को पढ ले, हम बिजली में भी सरप्लस होंगे

जयपुर। शेखावाटी के तीन जिलों (सीकर, चूरू और झुंझुनूं) तक यमुना का पानी लाने को लेकर 29 जून को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। एमओए के बाद सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर लौटे। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक रोड शो किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावटी के लोगों से कहा था कि हम यह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यमुना का पानी लेकर आएंगे। जिसके बाद हमारा किसान जरूर सोना पैदा करेगा।

राजस्थान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा

सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारी सरकार आई थी तो सबसे पहले हमने राजस्थान का रोडमैप बनाया कि सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। सभी की मांग थी कि राजस्थान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमारे किसान को पानी चाहिए, उद्योग को भी पानी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी जनता को चाहिए। हमारी कई परियोजनाएं 40-50 साल से लंबित थी।



ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं पर हमने पिछले ढाई साल में काम किया है।

कांग्रेस ने शेखावाटी के लोगों के साथ किया अन्याय

सीएम ने कहा कि आज मैं कांग्रेस के लोगों के बयान देख रहा था। वे 5 दिन पहले कुछ और कह रहे थे। हमने कहा कि इसका जवाब हम तभी देंगे, जब हमारा यह समझौता हो जाएगा।

लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं। शेखावाटी के लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। कांग्रेस के लोगों ने शेखावाटी के साथ जितना अन्याय किया, उतना किसी ने नहीं किया। जब वोट का समय आता था तो यह शिलान्यास कर देते थे। यमुना के पानी के सपने दिखाते थे। लेकिन इन्होंने आज तक इसे लेकर एक पत्र भी नहीं लिखा।

कांग्रेस ने हमेशा परियोजनाओं

हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल बंदी का तुरंत इलाज कराया। लालकोठी थाना पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच के अनुसार, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे एक बंदी को दूसरे बंदी ने टोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में

जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के बीच मारपीट:एक घायल, हनुमान चालीसा पढ़ने पर टोका; फिर नुकीली वस्तु से हमला करने का आरोप

पांचना-बांध विवाद पर हाईकोर्ट नाराज, कहा-पानी क्यों नहीं दे रहे: 15 दिन का दिया समय, कलेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा

जयपुर। पांचना बांध से पानी छोड़ने के विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा हैं। इस पर सरकार ने अदालती आदेश की पालना के लिए 15 दिन का समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए कहा कि अगर नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो कलेक्टर और संबंधित अधिकारी 27 जुलाई को कोर्ट में पेश हो जाए। यह निर्देश बेंच ने मंगलवार को विधायक रामकेश मीणा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

पिछले 21 साल से नहीं मिल

रहा पानी

वकील साराश सैनी ने कोर्ट को बताया कि पांचना



बांध से साल 1987 से 2005 तक कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा था लेकिन प्रदेश में गुर्जर आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने नहरों में पानी छोड़ना बंद कर दिया। जिसके कारण साल 2006 से नहरों के अंत

में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों (मुख्य रूप से मीणा बहुल) के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट साल 2020 और इसी साल अप्रैल-मई में नहरों में पानी छोड़ने का आदेश दे चुका हैं लेकिन प्रशासन करौली और सवाई माधोपुर जिलों के 74 गांवों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पिछले 20 सालों से चल रहा है। बांध के आस-पास के 39 गांवों (मुख्य रूप से गुर्जर बहुल) का कहना है कि बांध के निर्माण में उनकी जमीनी गई, इसलिए पहला हक उनका है, उन्हें डर है कि नहरों में पानी छोड़ने से उनके खुद के क्षेत्र में जल संकट गहरा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नहरों के अंत में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों (मुख्य रूप से मीणा बहुल) के किसानों को 2006 से सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। उनकी मांग है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहरों में तुरंत पानी छोड़ा जाए क्योंकि पानी नहीं मिलने से उन्हें हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला गरमा गया था। विवाद को लेकर गुड़ला-पांचना संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। हालांकि पांच दिन पहले सरकार के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया था।

कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर 11वें दिन प्रदर्शन

भूख हड़ताल कर रहे वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, पुलिस पर समर्थकों को रोकने के आरोप



नई दिल्ली। नीट पेपर लोक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का 11वें दिन भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच वहां तीन दिनों से भूख हड़ताल कर रहे लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। आंदोलन के आयोजकों ने बताया कि वांगचुक का ब्लड शुगर स्तर घटकर 66 पर पहुंच गया है, जो सामान्य से कम माना जाता है। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। समर्थकों और पार्टी के सदस्यों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है। कुछ लोगों को पहचान पत्र नहीं होने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया।

सोनम वांगचुक 170 दिन जोधपुर जेल में रहे
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक 170 दिन से वे जोधपुर जेल में थे। सोनम के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी। 90 लोग घायल हुए थे। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने इस हिंसा को भड़काया। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था।

दीपके का दावा- राजस्थान पैरामेडिकल का

जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर

बोले- सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं, ऑपरेशन सिंदूर उदाहरण; नए जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाला



नई दिल्ली। जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्विवेदी ने कहा- 'दो सालों में भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सतर्कता मजबूत बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज मैं यह जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वह एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं को कायम रखते हुए ईद ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। द्विवेदी की जगह जनरल धीरज सेठ ने ली है। उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया है। सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। उन्हें भारतीय सेना में लगभग चार दशक का अनुभव है। उन्होंने दिसंबर 1986 सेना ज्वॉइन की थी।

जनरल द्विवेदी ने कहा- भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर तैयारी रखी

जनरल द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती पूरी मजबूती और चौकसी के साथ रही। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने गंभीरता और संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर मामले में भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाए हैं, जिससे न्यू नॉर्मल की नई परिभाषा स्थापित हुई है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत हुआ है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा दृष्टिकोण, आपसी विश्वास और बेहतर समन्वय के साथ काम किया है।

बंगाल- हल्दिया रिफाइनरी के पास आग लगी, 1 की मौत

20 से ज्यादा घायल, पास से गुजर रही रेलवे लाइन पर भी असर, ट्रेन सर्विस प्रभावित

हल्दिया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सोमवार देर रात 2.45 बजे हल्दिया रिफाइनरी के पास भीषण आग लग गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर है। आग की चपेट में हल्दिया नगर पालिका के वार्ड-13 के चिरंजीबपुर इलाके के कई घर आ गए थे। पुलिस के मुताबिक, सभी पीड़ितों को हल्दिया सब-डिविजनल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पांच घायलों को तमलुक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया। आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई थीं। दोपहर 2 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। साउथ रेलवे के मुताबिक जहां आग लगी उसके पास से हल्दिया और दुर्गाचक लाइन गुजरती है। सुरक्षा के मद्देनजर अगले आदेश तक के लिए ट्रेन सर्विस रुक दी गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हल्दिया रिफाइनरी में आग लगने की खबरों को खारिज किया है।



पेपर जयपुर में लीक हुआ
पेपर लीक सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई परीक्षाएं अनियमितताओं का शिकार हो रही हैं। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल परीक्षा का पेपर भी जयपुर के कॉलेज से लीक हुआ। अगर आज आप

क्या जंतर-मंतर आने के लिए एक सामान्य नागरिक को पहचान पत्र की जरूरत होनी चाहिए। समर्थकों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए परिवहन व्यवस्था में भी बाधा डाली जा रही है।

अभिजीत दीपके फाउंडर, CJP

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विन्य डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से एथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश BPCL की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। BPCL ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा।

तया है एथेनॉल सप्लाई का विवाद

एथेनॉल सप्लाई का यह विवाद कर्नाटक की विन्य डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है। विन्य ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी थी कि उसका एथेनॉल बनाने का प्लांट है। इसकी सलाना उत्पादन क्षमता करीब 9.90 करोड़ लीटर है, लेकिन उसे केवल 3.92 करोड़ लीटर का आवंटन किया गया है। सरकार ने कहा था कि किसी कंपनी को पहले ज्यादा आवंटन मिला तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को हर बार उतनी ही मात्रा में आवंटन मिलेगा। हाईकोर्ट ने **BPCL** को खरीद कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा। इस आदेश के खिलाफ **BPCL** ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट रूम लाइव- अटॉर्नी जनरल- यदि एक सप्लायर का

एसआईआर पर 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लेटर लिखा डीएमके ने भी दस्तखत किए, बोले- चुनाव आयोग की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटींसिव रिवीजन (स्ट्रूक) प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा। DMK के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, जबकि लोकतंत्र का आधार सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देना है। लेटर पर कांग्रेस, वृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम समेत 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं।

एसआईआर प्रक्रिया से विभिन्न राज्यों में लोगों पर प्रभाव पड़ा

सूत्रों के मुताबिक, लेटर पर साइन करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वाम दलों के नेता शामिल हैं। लेटर में कहा गया है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं अपेक्षित तरीके से काम नहीं करतीं, तब देश की जनता न्यायपालिका की ओर उम्मीद से देखती है। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका और एसआईआर प्रक्रिया से विभिन्न राज्यों में लोगों पर पड़े प्रभाव की बात



कोटा बढ़ाया जाता है तो अन्य कंपनियां भी समान मांग लेकर अदालत पहुंच सकती हैं। इससे देशभर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है और नेशनल पॉलिसी प्रभावित होगी। एथेनॉल सप्लाई के अनुबंध अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप ले चुके हैं। 378 सप्लायर्स को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति का आवंटन किया गया था, जिनमें से 18 जून तक 680 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हो चुकी थी। अटॉर्नी जनरल: इसी तरह की कई याचिकाएं देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। इस मुद्दे पर अक्टूबर से पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि उसी समय एथेनॉल सप्लाई का नया एग्रीमेंट होना है।

सरकार बोली- 1.4 लाख करोड़ की बचत हुई

एसआईआर पर 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लेटर लिखा



की गई।
कांग्रेस महासचिव बोले- विपक्ष एकजुट है
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में लेटर भेजने का फैसला लिया गया था। **TMC** सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल बीजेपी को फायदा पहुंचाने और चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि

सीजेआई की टिप्पणी के बाद बनी सीजेपी, युवाओं को कॉकरोच कहा था
कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस टिप्पणी के अगले दिन, 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने सीजेपी की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए। 22 मई को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की, जिसे 8 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिलने का दावा किया गया। 10 जून तक सीजेपी ते इस्टाग्राम पर 2.27 करोड़ फॉलोअर्स थे। अब इसमें दो लाख की गिरावट आई है। फिर भी यह संख्या भाजपा के 94 लाख और कांग्रेस के 1.37 करोड़ फॉलोअर्स से ज्यादा है। एक्स पर सीजेपी के 2.79 लाख फॉलोअर्स हैं।

आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपका पेपर भी लीक हो सकता है और आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। सरकार और प्रशासन पेपर माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को रोकने पर ध्यान दे रहे हैं। आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम वायरस नहीं हैं, बल्कि उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन हैं। डबल इंजन वाली सरकार में डबल इंजन-डबल लोक हो रहा। दबाव और रोक-टोक के बावजूद प्रदर्शन जारी रहेगा।

छात्र संगठनों का भी समर्थन
प्रदर्शन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छह छात्र नेता भी शामिल हैं, जो अलग मंच से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

सरकार बोली- पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक एक्सपेरिमेंट असर अगले साल पता चलेगा: सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश

असर अगले साल पता चलेगा: सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा था- एथेनॉल सप्लाई बढ़ाने पर विचार करें
कर्नाटक हाईकोर्ट ने **BPCL**, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया था कि वे **VINP** डिस्टिलरीज एंड शुगर्स की 2025-26 के लिए ज्यादा एथेनॉल आवंटन की मांग पर विचार करें। कोर्ट ने कहा था कि सरकार की नीति के तहत बने ऐसे एथेनॉल प्लांट, जो सिर्फ ऑयल कंपनियों को एथेनॉल बेचते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म ऑफसेट एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली प्राथमिकता का लाभ मिलना चाहिए।

सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण योजना से कच्चे तेल का आयात कम हुआ है और देश को 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा

की बचत हुई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है और प्रदूषण भी कम हुआ है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले पूरा कर लिया है। 1 अप्रैल से पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिल रहा है। अब सरकार ने 2030 तक 30% एथेनॉल मिश्रण का नया लक्ष्य रखा है।

सरकार ने E20 को बताया सुरक्षित
हाल के दिनों में कुछ लोगों, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आशंका जताई है कि **E20** पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है और ईंधन दक्षता कम हो सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया है। तेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि **E20** ईंधन से वाहन इंश्योरेंस अमान्य

होने या वाहनों को नुकसान पहुंचने के दावों के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरक्षित, उपभोक्ता हितैषी और आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा

सरकार के मुताबिक, अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस योजना से भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, प्रदूषण कम हुआ है और किसानों को भी फायदा मिला है। भारत पिछले साल ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर चुका है। एक अप्रैल से पूरे देश में ई 20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब सरकार 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

कई नेता मौजूद रहे। वहीं उद्वग ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। रवबंधन हर 2 महीने में और मानसून सत्र के दौरान भी बैठक करेगा। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी।